विचार बिन्दु

मन जिस रूप की कल्पना करता है वैसा हो जाता है, आज जैसा वह है वैसे उसने कल कल्पना की थी। –योगवशिष्ठ

राजस्थान : सौर ऊर्जा का हब और भीषण गर्मी में बिजली की मारक कटौती

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल एक ओर जैसलमेर जिले में सौर उर्जा के एक बड़े निजी पार्क का उद्घाटन कर रहे थे और ठीक उसी समय राज्य के बिजली मन्त्री पोकरण में बिजली कटौती की शिकायत पर एक इन्जिनियर को सस्पेंड कर रहे थे, मानो इंजीनियर महोदय बिजली के उत्पादक हों। इसे कहते हैं बिजली के घर में अंधेरा। जो राजस्थान, भारत का सौर ऊर्जा का गढ़, 2025 में अपनी चमकती सौर परियोजनाओं और 24,102 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ देश में अव्वल है, उसी राज्य में बेइन्तिहा बिजली कटौती हो रही है चन्द गिने-चुने बड़े शहरों को छोड़ दें तो अधिकांश कस्बों और ग्रामीण इलाकों की हालत खराब है जिसमें गर्मी का अभी तो बस आरम्भ हुआ है और लोग बेहाल हैं।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक राज्य ने 118,359.51 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया, जिसमें सौर ऊर्जा का योगदान 43,572.46 मिलियन यूनिट रहा। यह आंकड़ा राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2023 और एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 की सफलता का प्रतीक तो है ही, जो 2030 तक 90 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखती है। भादला सौर पार्क जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स ने निश्चय ही राजस्थान को वैश्विक सौर ऊर्जा नक्शे पर ला खड़ा किया है। लेकिन इस चमक के पीछे एक अंधेरा सच छिपा है-बिजली कटौती, नए कनेक्शनों के लिए मारामारी, डिस्कॉम का भारी घाटा, उपभोक्ताओं को महंगी बिजली की सप्लाई, किसानों के लिए रात में बिजली आपूर्ति की अमानवीय व्यवस्था, और सौर परियोजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार। सौर ऊर्जा ने राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने का सुनहरा सपना दिखाया है।

राज्य की 29,858 मेगावाट की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा का हिस्सा 80 प्रतिशत से अधिक है। कुसुम योजना, रूफटॉप सौर प्रणालियां, और मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली की पहुंच बढ़ाई है। 2025 तक, 13 मिलियन से अधिक उपभोक्ता डिस्कॉम के नेटवर्क से जुड़े हैं, जो कुल ऊर्जा खपत का 30 प्रतिशत हिस्सा लेते हैं। भादला सौर पार्क, जो 2,245 मेगावाट बिजली पैदा करता है, और जैसलमेर व बाड़मेर जैसे क्षेत्रों में स्थापित सौर परियोजनाएं राज्य की प्रगति का प्रतीक हैं। लेकिन यह प्रगति केवल आंकड़ों तक सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सौर प्रणालियों की पहुंच मात्र 5.4 प्रतिशत है, जो शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों के साथ असमानता को उजागर करता है।

राज्य में सौर ऊर्जा क्षेत्र ने रोजगार सृजन में भी योगदान दिया है लेकिन वहां भी तकनीकी कुशल श्रमिकों को समुचित अवसर नहीं। 2025 तक, इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लगभग एक लाख नौकरियां पैदा हुई हैं लेकिन अधिकांश नौकरियां अस्थाई हैं। कुसुम योजना के तहत सौर पंपों की स्थापना और रखरखाव में स्थानीय तकनीशियनों को काम मिला है, जबकि सौर पार्क के निर्माण में अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिला है। लेकिन यहीं पर सौर पार्कं में स्थानीय अराजक तत्वों के आतंक ने हालात खराब कर रखे हैं मेरे एक परिचित ने इस पीड़ा को मुझ से शेयर करके बताया कि बाड़मेर, जैसलमेर में सौर उर्जा के पार्कं में कैसे गुन्डों ने हफ्ता वसूली का काम कर रखा है और सरकार को ये सब पता है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन स्कीम 2024 ने, स्टाम्प ड्यूटी में 75 प्रतिशत छूट और बिजली शुल्क में 100 प्रतिशत छूट जैसे लाभ देकर स्टार्टअप्स और छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन दिया है। लेकिन इन नौकरियों का बड़ा हिस्सा अस्थायी है, और कुशल श्रमिकों की कमी एक गंभीर समस्या आज भी बनीं हुई है।

सौर पैनल निर्माण और रखरखाव के लिए प्रशिक्षित तकनीशियनों की जरूरत को पूरा करने में सरकार नाकाम रही है। प्रशिक्षण केंद्रों की कमी और तकनीकी कौशल पर जोर न होने से यह क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहा। बिजली कटौती राजस्थान की एक पुरानी बीमारी है, जो 2025 में भी जनता को सता रही है। गर्मी के महीनों में, जब तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, शहरी क्षेत्रों में एयर कंडीशनर और कूलर की मांग ग्रिड पर भारी दबाव डालती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 7-8 घंटे की अनियोजित कटौती आम बात है। सौर ऊर्जा दिन में तो उपलब्ध है, लेकिन रात में बैटरी भंडारण की कमी इसे बेकार बना देती है। 2024 की नीति में 10,000 मेगावाट बैटरी भंडारण का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2025 तक केवल 500 मेगावाट की प्रगति हुई है जो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। यह सरकार की सुस्ती और प्राथमिकताओं के अभाव का नतीजा है।

सौर पैनल आपूर्ति व स्थापना में गुणवत्ता जांच को अनिवार्य किया जाए। 2025 में राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का सिरमौर है, लेकिन यह चमक केवल सतही है। राजस्थान को सही मायनों में सौर ऊर्जा का गढ़ बनाना है, तो सरकार को अपनी नाकामियों से सबक लेना होगा। पारदर्शी, जन-केंद्रित नीतियां और भ्रष्टाचार पर सख्ती ही इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं।

नए बिजली कनेक्शनों की मांग भी आसमान छू रही है। डिस्कॉम के पास 13 मिलियन से अधिक उपभोक्ता हैं, लेकिन नए कनेक्शनों के लिए महीनों की प्रतीक्षा और जटिल कागजी कार्रवाई ने जनता को हताश कर रखि है। कृषि क्षेत्र में डार्क जोन क्षेत्रों में कनेक्शन देना मुश्किल है, जिसके कारण किसान सौर पंपों की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन सौर पंपों की लागत और रखरखाव छोटे किसानों के लिए भारी बोझ है। कुसुम योजना के तहत सौर पंपों की स्थापना में भ्रष्टाचार की शिकायतें आम बात है सब्सिडी का लाभ बिचौलियों और प्रभावशाली लोगों तक सीमित है। डिस्कॉम का वित्तीय घाटा 2025 में बीस हजार करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। बिजली चोरी, पुराना ट्रांसमिशन नेटवर्क, और सब्सिडी योजनाएं इस घाटे के प्रमुख कारण हैं। ऊर्जा संचार में हानि 20 प्रतिशत से अधिक है, क्योंकि स्मार्ट ग्रिड और डिजिटल मीटरिंग सिस्टम की स्थापना में देरी हो रही है। इस घाटे का बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है, जो प्रति यूनिट 8-12 रुपये की दर से बिजली खरीद रहे हैं कामर्शियल उपभोक्ताओं को तो सबसे महंगी बिजली खरीदने को मजबूर हैं नतीजा राजस्थान में उद्योग-धंधों में निवेशकों की रुचि कम होती जा रही है। सौर ऊर्जा से उत्पादन लागत कम होने के बावजूद, इसका लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा है। इसका कारण है सौर परियोजनाओं में बड़े कॉरपोरेट्स का दबदबा और भ्रष्टाचार का जाल है।

सौर ऊर्जा क्षेत्र में बड़े कॉरपोरेट्स जैसे टाटा पावर और अदानी समूह की पकड़ मजबूत है। 2022 के निवेश राजस्थान शिखर सम्मेलन में टाटा पावर ने 8 हजार मेगावाट सौर परियोजनाओं और 1.50 लाख सौर पंपों की स्थापना का वादा किया था अदानी समूह ने 65 हजार करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की थी लेकिन इन परियोजनाओं का लाभ तीसरे पक्ष यानि अन्य राज्यों को बिजली निर्यात में जा रहा है, राज्य के हाथ कुछ नहीं लगा है। स्थानीय समुदायों को भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा नहीं मिल रहा, और उनकी जमीनें जबरन छीनी जा रही हैं। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि सौर परियोजनाओं के लिए भूमि अधिठाहण में स्थानीय अधिकारियों और कॉरपोरेट्स की मिलीभगत की शिकायतें आम हैं। सौर पैनल आपूर्ति और स्थापना में भी अनियमितताएं देखी जा रही हैं, जहां घटिया सामग्री का उपयोग कर मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है। किसानों के लिए सर्दियों में रात में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था अमानवीय है। 5 डिग्री से कम तापमान में रात को खेतों में सिंचाई करना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। यह व्यवस्था इसलिए लागू है ताकि दिन की बिजली शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों को मिल सके मतलब शहरों के पोषण से गांवों की बर्बादी।

कुसुम योजना ने कुछ राहत दी है, लेकिन केवल 20 प्रतिशत किसानों के पास सौर पंप हैं। सौर पंपों की स्थापना में देरी और भ्रष्टाचार ने इस योजना की साख को ठेस पहुंचाई है। सरकार की नाकामियां इस पूरे परिदृश्य को और गंभीर बनाती हैं। सौर ऊर्जा नीति 2023 और एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 कागजों पर क्रांतिकारी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत निराशाजनक है। बैटरी भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने में सरकार विफल रही है। ट्रांसमिशन नेटवर्क का आधुनिकीकरण सुस्त गति से चल रहा है। रूफटॉप सौर प्रणालियों की पहुंच बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान और वित्तीय योजनाएं अपर्याप्त हैं। किसानों की रात में बिजली आपूर्ति की समस्या को हल करने के लिए कोई ठोस नीति नहीं है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निगरानी और पारदर्शिता की कमी है। सौर परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों को हिस्सेदारी देने की बात तो की जाती है, लेकिन इसका अमल न के बराबर है। भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता का अभाव और स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी ने असंतोष को जन्म दिया है। इन समस्याओं का समाधान आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं।

बैटरी भंडारण प्रणालियों के लिए सब्सिडी और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना होगा। स्मार्ट ग्रिड और डिजिटल मीटरिंग सिस्टम में निवेश से ऊर्जा हानि को 10 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। रूफटॉप सौर को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान और आसान ऋण योजनाएं शुरू की जाएं। किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नई नीति बनाई जाए, और कुसुम योजना में भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई हो। सौर परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों को हिस्सेदारी दी जाए, और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। सौर पैनल आपूर्ति व स्थापना में गुणवत्ता जांच को अनिवार्य किया जाए। 2025 में राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का सिरमौर है, लेकिन यह चमक केवल सतही है। राजस्थान को सही मायनों में सौर ऊर्जा का गढ़ बनाना है, तो सरकार को अपनी नाकामियों से सबक लेना होगा। पारदर्शी, जन-केंद्रित नीतियां और भ्रष्टाचार पर सख्ती ही इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। जनता का भरोसा जीतने के लिए सिर्फ वादे नहीं, बल्कि जमीनी अमल की जरूरत है।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र मोहन शर्मा,
साहित्यकार, शिक्षाविद और चिन्तक

हार्वर्ड : सामुदायिक संस्थान की स्वायत्तता

एक राष्ट्रपति जो पुनः राष्टंपति चुने जाने में असफल होने पर अपने ही देश के संसद भवन 'केपीटोल' पर आक्रमण करवा सकता है वह अपने अहम् की तुष्टि के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पुनः राष्टंपति चुने जाने पर डोनाल्ड टंप अपने उपराष्ट्रपति जे.डी वांस की बात कि "विश्वव्रिद्यालय देश के दुश्मन हैं", को सही साबित करते हुए सभी विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम, विद्यार्थियों और प्राध्यापकों के चयन में प्रशासन के दखल को स्वीकार करने का आदेश जारी किया। बहाना अपने स्वनिर्मित आप्रवास नियमों को बना कर विदेशी विद्यार्थियों की भर्ती और प्राध्यापकों के चयन को प्रशासन के अनुसार करने के निर्देश जारी किए हैं। उनके अनुसार ये विश्वविद्यालय यहूदी विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन चुके हैं।

इसके जवाब में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रेसीडेंट एलन गार्बर ने अमरीकी प्रशासन के आदेश का प्रतिवाद करते हुए अमरीकी प्रशासन को लिखे अपने पत्र में लिखा है-

"हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमरीका की स्थापना से भी 140 साल पुरानी है। हार्वर्ड को 389 साल हो चुके हैं। यहां से पढ कर 8 राष्ट्रपति निकले हैं। सत्ता में रहने वाली कोई भी राजनीतिक पार्टी हमें यह निर्देश नहीं दे सकती कि हमें क्या पढाना है और कैसे पढाना है और किसे नियुक्ति देनी है।"

"टंप सरकार ने युनिवर्सिटीज को अपनी नीतियों में बदलाव के आदेश दिये हैं। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमरीकी संविधान से मिली स्वतन्त्रता के अधिकार को गिरवी नहीं रखेगी। कोई भी यूनिवर्सिटी अभिव्यक्ति की आजादी का केंद्र होती है। यूनिवर्सिटी होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग हैं। भयमुक्त समाज और सभी के लिए खुशहाल जीवन के लक्ष्य यूनिवर्सिटी में बरसों से बनाये रखा है। हम हमेशा किसी भी नस्ल 'यहूदी' अथवा धर्म के त्रिरूद्ध भडकाऊ प्रदर्शनों के खिलाफ रहे हैं। पिछले पंद्रह महिनों के दौरान हमने ऐसे प्रयास किये है कि दुनिया रहने के लिए एक बेहतर जगह बने। हार्वर्ड का लक्ष्य है बहुलवादी समाज के लिए काम करना। दकियानूसी सोच का हमेशा विरोध किया जायेगा। हार्वर्ड का प्रयास वैज्ञानिक सोच को विकसित करने का है। इन सब के बीच सरकार की ओर से जारी होने वाले सभी आदेशों का यूनिवर्सिटी ने पालन किया है।

"यूनिवर्सिटी से जुड़े 11 कॉलेज इस दिशा में काम कर रहे हैं। यह बात अमरीका ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हमेशा से सरकार के साथ खुले संवाद के लिए तैयार है। लेकिन, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम किसी भी अनुचित दबाव के आगे झुकने वाले नहीं है फिर चाहे कोई भी सरकार सत्ता में हो।" इसके बाद टंप प्रशासन ने 19 हजार करोड़ डॉलर की सहायता-अनुदान रोक दिया है तथा हार्वर्ड युनिवर्सिटी की आमदनी से इनकम टैक्स वसूलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 2.2 बिलियन डॉलर की सरकारी सहायता को तत्काल रोक दिया गया है जिसके विरूद्ध हार्वर्ड संस्थान न्यायालय में दावा पेश कर चुका है। हार्वर्ड के इस पूरे प्रकरण में हार्वर्ड के प्रेसीडेंट एलेन गार्बर के पत्र का विशेष महत्व है जो हार्वर्ड की स्वायत्त सामुदायिक संस्थान की पैरवी करते हुए शक्तिशाली अमरीकी प्रशासन के सामने तनकर खड़ा हो रहा है।

'सामुदायिक संस्थान' निश्चित रूप में सरकारों की स्वार्थपरक, अहंकारी, व्यक्तिवादी अपेक्षाओं के बीच सामुदायिक महत्व और सामुदायिक उत्तदायित्वों को रेखांकित करती है। संयुक्त राज्य अमरीका के औपचारिक गठन और संविधान को अपनाने के बावजूद, बेशक हार्वर्ड जैसी संस्थान पूंजीवादी शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, फिर भी जिस स्वरूप में इसका विकास हुआ है वह भविष्य की वैश्विक सामुदायिक संस्थान के रूप में उभर चुकी है और अगर इसके पूंजीगत आग्रहों को एक तरफ रख दिया जाये तो हार्वर्ड भविष्य की कम्यूनिस्ट व्यवस्था के सामुदायिक संस्थान की अभिव्यक्ति है जो किसी पूंजीवादी सरकार के प्रशासनिक पूर्वाग्रहों को नकारते हुए मानवजाति के सामुदायिक सरोकारों को स्थापित करते हैं। यदि हम सोवियत संघ की व्यवस्था में सरकार द्वारा प्रोत्साहित सामुदायिक संस्थानों के किये गये विकास को छोड़ भी दें तो, यूरोपीय संघ उसी सोवियत संघ की प्रेरणा को आगे बढा रहा है जहां अनेक संस्कृतियों और अनेक राष्ट्रों तथा राष्टीयताओं के होते हुए भी उनके समान आर्थिक, सामरिक हित है निश्चित ही यह भविष्य की विश्वव्यापी स्वायत्त सामुदायिक संस्थानों के लिए नींव का पत्थर है- हार्वर्ड का टंम्प प्रशासन जैसे शासन के सामने अपनी स्वायत्तता, अपनी वैश्विक पहचान बनाये रखने के लिए।

-राम निवास बैरवा,
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

पहलगाम आतंकी हमला: राजनीतिक नजरिये से बहुत कुछ मायने रखता है!

श्याम सिंह पंवार

कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला के बारे में बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर गोलीबारी की, निश्चित रूप से एक निंदनीय और अमानवीय कृत्य है। यह घटना न केवल धार्मिक आधार पर नफरत और हिंसा को दर्शाती है, बल्कि "राजनीतिक दृष्टिकोण से भी गहरे निहितार्थ रखती है।"

धार्मिक आधार पर यह हमला नफरत और कट्टरता का प्रतीक है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आतंकियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया और कुछ मामलों में जबरन कलमा पढने के लिए दबाव डाला, जो न मानने वालों को गोली मार दी गई। यह कृत्य किसी भी धर्म के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि सभी धर्म मानवता, शांति और सह-अस्तित्व की बात करते हैं। इसे किसी "धार्मिक चोले में ढालना केवल हिंसा को औचित्य देने की कोशिश है, जो किसी भी नैतिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं है।"

राजनीतिक दृष्टिकोण से यह हमला कश्मीर में शांति और पर्यटन के पुनरुत्थान को अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है। पहलगाम, जिसे 'मिनी स्विटजरलैंड' कहा जाता है, पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है, और हाल के वर्षों में कश्मीर में पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह हमला, क्षेत्र में अशांति फैलाने और भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास हो सकता है।लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (ऊँइ) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, और सूत्रों के अनुसार, आतंकी पाकिस्तान से संचालित हो सकते हैं।

इस हमले ने कश्मीर के पर्यटन उद्योग पर गहरा आघात पहुंचाया है, क्योंकि कई पर्यटक क्षेत्र छोड़ रहे हैं। अगर ऐसे नजारे और बढ़े तो यहाँ के लोगों का रोजगार प्रभावित हो जाएगा।

यह मेरा निजी विचार है कि– यह हमला न केवल धार्मिक कट्टरता का घिनौना प्रदर्शन है, बल्कि "एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति भी प्रतीत होती है। जो कि मानवता के खिलाफ एक जघन्य अपराध है।"

-श्याम सिंह पंवार, कानपुर।
वरिष्ठ पत्रकार

दो नाबालिगों का विवाह रूकवाया

उदयपुर, (कासं)। जिला कलक्टर नमित मेहता के निर्देशन में जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रशासन पूर्ण मुस्तैदी से जुटा हुआ है। कलक्टर कार्यालय में स्थापित बाल विवाह कन्ट्रोल रुम एवं बाल अधिकारिता विभाग में संचालित चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 पर बेडवास में बाल विवाह की सूचना पर पहुंच कर दो नाबालिगों का विवाह रूकवाया।

कन्ट्रोल रुम प्रभारी बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक के.के.चंद्रवंशी के अनुसार मंगलवार शाम चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर जानकारी मिली कि शहर के समीप बेडवास क्षेत्र में एक परिवार अपने नाबालिग बालक और बालिका की शादी 22 अप्रेल 2025 को करने जा रहे है। चन्द्रवंशी ने चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक नवनीत ओदिच्य को तुरंत टीम गठित कर प्रशासन के सहयोग से बाल विवाह रुकवाने एवं पाबन्द करवाने के निर्देश दिए। चाइल्ड हेल्पलाइन सदस्य महेंद्र सिंह राजपूत, प्रदीप मेघवाल, पटवारी आशीष कुमार, प्रताप नगर थाना से ए.एस.आई पर्वत सिंह और बाल कल्याण समिति से अध्यक्ष यशोदा पणिया, सदस्य अंकुर टांक मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। प्रथम दृष्ट्या लगा कि शादी की पूरी तेयारी थी। टेंट लगे हुए थे और खाना चल रहा था।

विवाह के बारे में पूछा तो आना-कानी करने लगे फिर दूल्हा और दुल्हन के दतावेज देखे तो बालिका की उम्र 17 वर्ष पाई गई। दो बालक की उम्र 16 वर्ष व 18 वर्ष थी दोनों नाबालिग पाए गए। इस पर टीम ने लडकी के परिवार को उसके बालिग होने के बाद ही शादी करने के लिए पांबद किया। इस कार्यवाही में बाल कल्याण समिति यशोदा पणिया, सदस्य अंकुर टांक, चाइल्ड हेल्पलाइन टीम से मोईन मन्सुरी महेंद्र सिंह और प्रदीप मौजूद रहे।

ग्रीन लिटिल बेबी श्रेया कुमावत की अनोखी पहल : धरती माता को हरा-भरा और स्वच्छ बनाने का संकल्प

शाहपुरा। पर्यावरण प्रेमी ग्रीन लिटिल बेबी श्रेया कुमावत द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में, नन्हे-मुन्ने बच्चों के साथ पर्यावरण संरक्षण के महत्व की चर्चा की गई। कार्यक्रम में धरती माता को हरा-भरा, स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रखने का संकल्प लिया गया।ठीन लिटिल बेबी श्रेया कुमावत ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर दिया।कार्यक्रम में बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत अपने घर को हरा-भरा करने और अपने जन्मदिन एवं किसी खास दिन पर पेड़ लगाने का संकल्प लिया।प्लास्टिक प्रदूषण के कारणों और इसके निवारण के तरीकों पर चर्चा की गई।श्रेया कुमावत ने कहा, प्लास्टिक प्रदूषण हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और प्लास्टिक को रिसाइकिल करना चाहिए।

ग्रीन लिटिल बेबी श्रेया कुमावत ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

सभी बच्चों को ग्रीन बेबी का मेडिसिन हर्बल गार्डन का भ्रमण कराया गया और उसमें लगे प्रत्येक हर्बल प्लांट्स के बारे मे और घर की शुद्ध आर्गेनिक सब्जीयों के पौधों के बारे में एवं घर से निकले 80 वेस्ट कचरे व प्लास्टिक को रिसाइकिल कर वेस्ट तो बेस्ट उपयोग करने के बारे में जानकारी दी गई। हमें अपने घर को हरा-भरा करने के साथ और अपनी धरती माता पर भी पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश

- **अब संतों, जननायकों और शहीदों के नाम होंगी अजमेर शहर की प्रमुख सड़कें**
- **संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी ने दी हरी झंडी, चार प्रमुख सड़कों का नामकरण**

अजमेर (कासं)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की चार प्रमुख सड़कों का नामकरण किया गया है। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी ने नामकरण के इन प्रस्तावों को हरी झंडी दी। संत शिरोमणी नामदेव महाराज, शहीद स्व. मेजर नटवर सिंह शक्तावत, शहीद अविनाश माहेश्वरी, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर अब यह सड़कें जानी जाएगी। शीघ्र ही अन्य मार्गों, थानों व क्षेत्रों के नाम भी राष्ट्र गौरव के परिचायक नामों के आधार पर रखे जाएंगे।

अजमेर शहर को गुलामी के प्रतीक नामों से मुक्ति दिलाने और राष्ट्रनायकों को जनमानस में स्थापित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के क्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रशासन को यह निर्देश दिए थे।

उन्होंने कहा था कि अजमेर के लोगों, विशेषकर युवा पीढ़ी में अपने नायकों के इतिहास, नाम और उनके व्यक्तित्व की पहचान और जानकारी होनी चाहिए। देवनानी ने निर्देश दिए थे कि आगरा गेट चौराहे से लेकर अग्रसेन चौराहे तक मार्ग का नाम संत शिरोमणी नामदेव महाराज के नाम से किया जाए। इसी तरह सेंट स्टीफन चौराहे से झलकारी बाई स्मारक तक की रोड़ का नाम वीरांगना झलकारी बाई रोड़ एवं पंचशील नगर में एक्सिस बैंक के भवन से ब्राविया रेजिडेन्सी तक सेक्टर बी व सी के मध्य की डिवाईडर रोड़ का नाम शहीद स्व. मेजर नटवर सिंह शक्तावत तथा आनासागर पुलिस चौकी से मामा की दुकान (प्रेमनगर) तक स्थित मार्ग का नाम शहीद अविनाश माहेश्वरी मार्ग किया जाए। इस सभी प्रस्तावों को नगर निगम की साधारण सभा में भी मंजूरी दे दी गई।

देवनानी के निर्देश पर इन नामों को संभागीय आयुक्त महेश चन्द्र शर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने भी मंजूरी दे दी है। इन मार्गों को अब संतों, वीरांगना व जननायकों के नाम से जाना जाएगा। गौरतलब है कि देवनानी के निर्देश पर इससे पूर्व अजमेर में भवनों व तालाबों को गुलामी के प्रतीक नामों से मुक्ति दिलाई गई थी। देवनानी के निर्देश पर किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदल कर महर्षि दयानन्द विश्रांति गृह किया गया। इसी तरह राजस्थान पर्यटन विकास निगम की होटल खादिम का नाम बदल कर होटल अजयमेरू किया गया। इसी तरह शहर के प्रमुख तालाब फॉयसागर को भी अंग्रेजी नाम से मुक्ति दिलाकर वरूण सागर नाम दिया गया। देवनानी ने एलीवेटेड रोड़ का नाम बदल कर रामसेतु करने पर भी विधायक के रूप में अपनी सहमति दी है।

राशिफल गुरूवार 24 अप्रैल, 2025

पंडित अनिल शर्मा

वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2082, शतभिषा नक्षत्र दिन 10:49 तक, ब्रह्म योग दिन 3:56 तक, बालव करण दिन 2:33 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 3:26 से मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-मेष, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज बरुथिनी एकादशी व्रत, पंचक है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः शुभ सूर्योदय से 7:35 तव, चर 10:48 से 12:25 तक, लाभ अमृत 12:25 से 3:38 तक, शुभ 5:15 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 5:58, सूर्यास्त 6:51

मेष
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी।

सिंह
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा।

धनु
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कन्या
व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। नवीन कारोबारी अनुबंध प्राप्त होंगे। आवश्यक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

मकर
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक यात्रा संभव है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

तुला
व्यक्तिगत परेशानियां दूर होने लगेंगी। मन का भय समाप्त होगा। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनःस्थिति में सुधार होगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कर्क
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। व्यावसायिक मामलों में संयम रखना ठीक रहेगा।

वृश्चिक
घर-परिवार में धार्मिक-मांगलिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

मीन
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।